

July to October



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, २ जुलाई, १९९७/११ आषाढ़, १९१९

हिमाचल प्रदेश सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, २५ जून, १९९७

संख्या एम० ए० (३)-१/९६.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में विधि अधिकारी वर्ग-II (राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपावन्ध "अ" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग विधि अधिकारी वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, १९९७ है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

हर्ष गुप्ता,  
वित्तियुक्त एवं सचिव।

उपाबन्ध "अ"

कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश में विधि अधिकारी (वर्ग-II) के राजपत्रित पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

- |  |   |
|--|---|
| 1. पद का नाम                                       | विधि अधिकारी                              |
| 2. पदों की संख्या                                  | 1 (एक)                                    |
| 3. वर्गीकरण  | वर्ग-II (राजपत्रित)                       |
| 4. वेतनमान   | ह0 2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3500. |
| 5. चयन पद अथवा अचयन पद                             | चयन                                       |
| 6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु। | 35 वर्ष से कम :                           |

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में

आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्तवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेनित किये गए हैं/किये गये थे।

टिप्पणी (1).--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

टिप्पणी (2).--अन्यथा मुअह्रित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार जितनी की जा सकेगी।

1. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।

(क) अनिवार्य:

(i) भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में व्यावसायिक उपाधि या इसके समकक्ष।

(ii) अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हताएं:

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और कोच्चियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।

आयु : लागू नहीं

शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अतिरिक्त ऐसी और अतिरिक्त के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा मन्त्र प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

भर्ती की पद्धति.--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

ज्ञा-प्रतिज्ञा प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।

विधि सहायकों में से, जिनके पास विधि में व्यवसायिक उपाधि हो और जिनका विधि सहायक के रूप में पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या (31-3-91 तक की गई) लगातार तदर्थ सेवा सहित उक्त सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा

परन्तु विधि अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए, विधि सहायक के पद के वर्तमान पदधारी पर विचार करके उसकी उपयुक्तता के अध्यधीन आरम्भिक कांडर गठित किया जाएगा।

- (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सभी पदों में 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिये इत्युक्त अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी कि उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निदिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर हो जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों को जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम ग्रहता सेवा या पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिस डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्स परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेंसीज इन हिमाचल स्टेट नान टेक्निकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एकत्र सर्विसमें (रिजर्वेशन आफ वेकेंसीज इन दो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो --

टिप्पणी. (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति नियुक्ति से पूर्व 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी :

परन्तु 31-3-91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरवर्तित होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या इसके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जायेगी ।

भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है

सीधी भर्ती किए जाने वाले बाह्यियों के लिए अपेक्षा ।

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है:—

- (क) भारत का नागरिक, या
- (ख) नेपाल की प्रजा, या
- (ग) भूटान की प्रजा, या
- (घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 में पूर्व भारत में स्थाई निवास के आशय से आया हो, या

- (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पहले तांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मालवा, जेयरे और इथोपिया से भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया है :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो । ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/माशुक्कार में के प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा ।

सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति आयोग/अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

#### 16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

#### 17. विभागीय परीक्षा

(1) सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1976 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी, अन्यथा वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा :—

- (i) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए,
- (ii) परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् भी स्थायीकरण के लिए; और
- (iii) अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए :

परन्तु उस अधिकारी से जिसने इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व किन्हीं नियमों के अधीन पूर्णतः या अंशतः विभागीय परीक्षा पारित की है यथास्थिति पूर्णतः या अंशतः परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए, इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उससे इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए, इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी, उससे 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्

- (i) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए, और
- (ii) परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्थायीकरण के लिए प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति को सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि

उसने निम्नतर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही पारित कर ली हो।

(3) सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करके, विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या भागतः छूट मंजूर कर सकेगी, परन्तु यह तब जब तक कि ऐसे अधिकारी पर उसकी अधिवर्धिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से पूर्व किसी अन्य उच्चतर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना सम्भाव्य न हो।

8. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श के आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

*Authoritative English text of this Government Notification No. Agr.-A (3)-1/96, dated the 25th June, 1997 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.*

## AGRICULTURE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 25th June, 1997*

**No. Agr.-A-(3)-1/96.**—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Law Officer, Class-II (Gazetted) in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Agriculture Department, Law Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,

HARSH GUPTA,

*Financial Commissioner-cum-Secretary.*

## ANNEXURE "A"

## RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LAW OFFICER CLASS-II (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, HIMACHAL PRADESH

- |  |   |
|--|---|
| 1. Name of the post                              | Law Officer                               |
| 2. Number of posts                               | 1 (One)                                   |
| 3. Classification                                | Class-II (Gazetted)                       |
| 4. Scale of pay                                  | Rs. 2000-60-2060-70-2250-75-3000-100-3500 |
| 5. Whether selection post or non-selection post. | Selection                                 |
| 6. Age for direct recruitment                    | Below 35 years:                           |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the



post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H. P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment.

(a) *Essential qualification :*

(i) Should possess a professional Degree in Law from a recognised University in India or its equivalent.

(ii) At least 5 years experience as an Advocate.

(b) *Desirable Qualifications :*

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.

(i) *Age :* No

(ii) *Educational qualifications :* No

9. Period of probation, if any

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.

100% by promotion failing which by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.

By promotion from amongst the Legal Assistants who possess professional degree in Law and also possess five years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1991) service, as Legal Assistant:

Provided that the initial cadre shall be constituted by considering the present incumbent of the post of Legal Assistant for promotion to the post of Law Officer subject to his fitness.

(1) In all cases of promotion, the *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these

rules for promotion subject to the condition :—

- (i) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-91) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

*Explanation.*—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *Ex-service-men* recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of *Ex-servicemen* (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

- (2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:

Provided that *inter-seniority* as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
14. Essential requirements for a direct recruitment.

To be presided over by the Chairman, H. P. Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

As required under the law

A candidate for appointment to any service or post must be:—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malwa, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

## 16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

## 17. Departmental Examination

(1) Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall

not be eligible to:—

- (i) Cross the efficiency bar next due;
- (ii) Confirmation in the service even after completion of probationary period; and
- (iii) Promotion to the next higher post :

Provided that an officer who has qualified the Departmental Examination in whole or in part prescribed under any rules before the notification of these rules shall not be required to qualify the whole or in part, of the examination as the case may be;

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the 1st March, 1976, shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules :

Provided further that an officer for whom no Departmental Examination was prescribed prior to the notification of these rules and who had not attained the age of 45 years on 1-3-1976, shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules after attaining the age of 50 years for the purpose of (i) crossing of efficiency bar next due, and (ii) confirmation in the service after completion of probationary period.

(2) An Officer on promotion to higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(3) The Government may, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing exemption in accordance with the Departmental Examination Rules to any class or category of persons from the departmental examination in whole or in part provided that such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

#### 18. Powers to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.